राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4803/2017

बीरबल राम विश्नोई पुत्र श्री सुख राम, निवासी वीपीओ तिलवासनी, वाया भावी, तहसील पीपर सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जिला बीकानेर, राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, खोजा, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री कैलाश जांगिड़
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री सरवन कुमार श्री सुनील पुरोहित

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>23/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों की निष्क्रियता से उपजी है, जिन्होंने उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर उसे शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक ग्रेड-III ('पीटीआई ग्रेड-III') के पद पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया, जबकि उसने ओबीसी श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

2. रिट याचिका में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ('आरपीएससी') द्वारा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के तहत पीटीआई ग्रेड-II और III के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले दिनांक 18.09.2013 के विज्ञापन के अनुसार, अपेक्षित योग्यता रखने वाले याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी में इसके लिए आवेदन किया था। परीक्षा में भाग लेने के बाद, उसने ओबीसी श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए।

2.1. याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। इसके बाद प्रतिवादी आरपीएससी ने संशोधित परिणाम जारी किया और 16.12.2016 को पीटीआई ग्रेड-II और III के पद के लिए कट ऑफ घोषित किया, जिसमें याचिकाकर्ता का रोल नंबर पीटीआई ग्रेड-III के पद के लिए शामिल किया गया। प्रतिवादियों ने 31.01.2027 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी किया और उसे उक्त पद पर राजकीय सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, खोजा, पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया।

2.2. नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.02.2017 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, साथ ही शपथ पत्र भी दिया, जिसमें उसके खिलाफ धारा 143, 380, 420, 467, और 471 आईपीसी के तहत कथित अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 244/2005 दर्ज होने का खुलासा किया गया। प्राचार्य ने याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। डीईओ ने याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा बचाव में यह तर्क दिया गया है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रतिवादियों की कार्रवाई पूर्णतः वैध, न्यायोचित और कानून के अनुसार है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या दोष नहीं है और यह संधारणीय है। इस संबंध में कार्मिक विभाग (ग्रुप-2), जयपुर ने सरकारी नौकरियों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के विषय पर दिनांक 04.12.2029 को परिपत्र जारी किया है।

3.1. नियोक्ता निश्चित रूप से उस जॉब प्रोफ़ाइल को ध्यान में रख सकता है, जिसके लिए चयन किया गया है, अभ्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की गंभीरता और क्या प्रश्नगत दोषमुक्ति सम्मानजनक दोषमुक्ति थी या केवल संदेह के लाभ के आधार पर या संयोजन के परिणामस्वरूप थी।

3.2. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की नैतिक अधमता से संबंधित धारा के तहत एक आपराधिक मामला है। ऐसे मामले में, उत्तर देने वाले प्रतिवादी संज्ञान लेने और आरोप तय करने के आधार और विभिन्न अन्य पहलुओं, याचिकाकर्ता के समग्र आचरण सहित लगाए गए आरोपों पर विचार करने के लिए बाध्य हैं। समग्र सत्यापन पर, याचिकाकर्ता के पिछले रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं पाए गए।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों की प्रतिस्पर्धी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक निर्णय पर भरोसा किया है, जो संयोगवश मेरे द्वारा दीपक मिस्त्री बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6457/2023 नामक मामले में कुछ हद तक समान परिस्थितियों में लिखा गया था, जो 12.07.2024 को निर्णीत किया गया, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "7. आइए हम प्रतिस्पर्धी तर्कों की जांच करें। मुख्य रूप से, उसके खिलाफ मुकदमे की लंबितता याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र को रोकने का एकमात्र कारण प्रतीत होता है। निस्संदेह, लंबित मुकदमे में विचाराधीन व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, क्योंकि अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में संदेह अक्सर तब तक छाया रहता है जब तक कि उन्हें बरी नहीं कर दिया जाता। नतीजतन, वे आम तौर पर दोषी साबित होने तक निर्दोषता के अनुमान से लाभ नहीं उठाते हैं। हालांकि, विचाराधीन व्यक्ति की कथित भूमिका की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है, खासकर अगर इसमें नैतिक अधमता शामिल है जो संभावित नियुक्ति से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
>
> 8. इस मामले में, यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता ने खुद ही एफआईआर दर्ज करवाई थी और इस प्रकार, वास्तव में, वह खुद पीड़ित था। वह भाग्यशाली था क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था जैसा कि एफआईआर कथन में कहा गया है। इसके अलावा,

उसका पीड़ित होना घटना के आस-पास की परिस्थितियों से उपजा है, जहाँ मृतक, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी- जैसा कि सुनवाई के दौरान भरोसा किया गया) के अनुसार नशे की हालत में पाया गया था, वह एक मोपेड चला रहा था जो याचिकाकर्ता की मोटरसाइकिल से टकरा गई।

9. इस परिस्थिति में, यह याचिकाकर्ता के लिए एक भाग्यशाली परिणाम प्रतीत होता है, जो उस घातक परिणाम से बाल-बाल बच गया जो उसके लिए भी आसानी से घातक हो सकता था। जीवित याचिकाकर्ता अब खुद को मुकदमे का सामना करते हुए पाता है, मृतक के विपरीत जो दुखद रूप से अपनी चोटों के कारण मर गया और, जाहिर है, नशे की हालत के कारण दुर्घटना में योगदान दिया। जो भी हो, यह मुकदमे का विषय है।

10. संक्षेप में, मुकदमे का लंबित होना याचिकाकर्ता की पीड़ितता और दुर्घटना में उसके सौभाग्य से बचने को और बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है।

11. अंततः, एक बार फिर नियम 18 को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की आपराधिक कार्यवाही में शामिल होने की परिस्थितियाँ नैतिक पतन का गठन नहीं करती हैं या अन्यथा उन कर्तव्यों पर प्रभाव नहीं डालती हैं जिन्हें याचिकाकर्ता से निभाने की उम्मीद की जाती है, अगर नियुक्ति की पेशकश की जाती है। इसके अतिरिक्त, युवावस्था में अविवेक जरूरी नहीं कि आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता हो; इसलिए, ऐसे मामलों को संबोधित करने में सुधारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

12. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि यह पता चलता है कि 19.05.2023 के आदेश के अनुसार,

प्रतिवादियों को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन एक पद खाली रखने का निर्देश दिया गया था।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति आपराधिक कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगी और यदि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जाता है, तो परिणाम भुगतने होंगे।"

6. इसमें कोई संदेह नहीं कि उपरोक्त मामले में अपराध की प्रकृति अलग थी। ऐसा कहने के बाद, यह पता चलता है कि वर्तमान मामले में भी विवाद सिविल प्रकृति का है, लेकिन आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी नहीं लगता है और उसे सह-आरोपी के रूप में रखा गया है। जो भी हो, जालसाजी आदि के आरोप परीक्षण का विषय हैं।

7. इस मामले का एक और पहलू यह है कि जहां तक उपरोक्त कार्यवाही के खुलासे का सवाल है, याचिकाकर्ता पर न तो कोई गलत बयानी का आरोप लगाया गया है और न ही कोई छिपाने का आरोप लगाया गया है। ये मामले 04.08.2005 को शुरू किए गए थे। तब से लगभग 20 साल बीत जाने के बावजूद, मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है और अभी भी प्रारंभिक चरण में है।

8. परिस्थितियों की समग्रता में, मेरा मानना है कि रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के प्रदर्शन का लाभ दिया जाए और अंतरिम आदेश के तहत रिक्त रखे गए पद को नियुक्ति पत्र जारी करके उसे आवंटित किया जाए। हालांकि, नियुक्ति पत्र में एक विशेष खंड डाला जाएगा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे के अंतिम परिणाम के अधीन है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा से बाहर रहने की अवधि के दौरान, उन्हें काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वरिष्ठता और आभासी लाभ उन्हें उनके समकक्षों के साथ समानता के आधार पर दिए जाएंगे, जिनके साथ उन्होंने उसी चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा की थी।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।